(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के कब तक हटा लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा. बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से एक मण्डी हस्तक्षेप योजना को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है, जिसमें 1-1-92 से 29-2-92 तक की अवधि में 30,000 मीटरी टन अच्छी औसत किस्म की प्याज की खरीद 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। यह खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राज्य द्वारा मनोनीत एजेंसी द्वारा बराबरी के आधार पर की जायेगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत की गयी है कि राज्य सरकार पिछले वर्षों की हानियों सहित हानियों का वहन केन्द्र सरकार के साथ बराबरी के आधार पर करेगी और राज्य एजेंसी नियुक्त करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के मान-दण्डों के संबंध में अभी तक अपनी सहमति सूचित नहीं की है।

(घ) आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अधीन, प्याज खुले सामान्य लाइसेंस (4) की श्रेणी में आता है और इसका निर्यात नेफेड के माध्यम से किया जाता है, जो सम्बद्ध जहाज व्यापारियों के साथ प्याज का निर्यात करते हैं। इस प्रकार, प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

74*[*Transferred to the 5th March,*

Food famine in Tripura

*75. DR. BAPU KALDATE :
SHRI M.S. GURUPADASWAMY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have made any on-the-spot assessment of the food famine in the inaccessible and remote villages in Tripura leading to starvation deaths;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what measures have been taken by Government to provide relief to the affected areas to prevent starvation deaths?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) Senior Officials of Government of Tripura have visited inaccessible and remote villages. No case of starvation death has been reported from these villages.

(c) The State Government is implementing various schemes like Jawahar Rojgar Yojana and State Rural Employment Programme in all parts of Tripura particularly covering the hilly and interior areas to generate employment to the rural poor. Adequate availability of foodgrains is also ensured in critical areas by the State Government.

उत्तर प्रदेश में यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्त-पोषित कृषि परियोजनाएं

*76. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कृषि परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ; जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) इस प्रकार की सहायता के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित दो चल रही कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय

आर्थिक समुदाय की सहायता प्रदान की गई है :—

(1) उत्तर प्रदेश में चंबल/यमुना के जल ग्रहण क्षेत्रों के बीहड इलाकों में समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

(2) उत्तर प्रदेश में भीमताल समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

(ख) ऐसी सहायता से कोई जिलावार लक्ष्य नहीं है । पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91 तक) के दौरान चम्बल/यमुना परियोजना के लिए दी गई यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता 2832.84 लाख रुपए है ।

भीमताल परियोजना 1990-91 से जिला नैनीताल में चलाई जा रही है । इस परियोजना के लिए अभी तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कोई सहायता नहीं दी गई है ।

Sharing of river waters with Bangladesh

*77. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India and Bangladesh have agreed on sharing of waters of four common riv ers;

(b) if so, whether any guiding principles have been enuciated in this regard; and

(c) the outcome of the recent discussions held at Delhi?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA) : (a) and (b) It has been proposed that initially the four rivers-namely Meghana, Brahmaputra, Teesta and Ganga will be considered together for considering the sharing of waters between India and Bangladesh so that deficits in one can be met with from the quantities available in the other.

(c) In the Secretary level discussions held at Delhi in October, 1991, it was agreed that a joint observation station to monitor the flows of the Tista river would be established on the Indian side near the border. Bangladesh side gave a draft operational plan for long-term sharing of waters of the river Tista between Bangladesh and India and the Indian side presented the possibilities of formulating a comprehensive arrangement for sharing of river waters based on a long-term perspective.

Financial grant to fake colleges in Bihar

*78. SHRI YASHWANT SINHA :
SHRI S.S. AHLUWALIA :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be based to state:

(a) the total grant made available to colleges in Bihar by the UGC during the 7th Five Year Plan, University-wise and year-wise;

(b) whether it is a fact that some amount of this grant has gone to fake colleges;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) :(a) According to the information furnished by UGC, the Commission provided the following grants to eligible colleges in Bihar, University-wise, during the 7th Plan:—

Name of the University	No. of eligible colleges	Plan grants sanctioned during the 7th Plan (Rs. in lakhs)
1. Bhagalpur	27	110.39
2. Bihar	55	211.38
3. K.S. Darbhanga	NIL	..
4. L.N. Mithila	65	235.87
5. Magadh	59	310.44
6. Patna	5	22.97
7. Ranchi	52	250.00